उपनिवेशवाद 1757 से पहले की
राजनैतिक अराजकता को समाप्त कर केवल
शान्ति व व्यवस्था स्थापित करना चाहता
है। वाणिज्यिक औपनिवेशिक हितों की स्थापना
के लिये इस निकाय की स्थापना जरूरी थी। जहाँ
तक व्यावहारिकता का प्रश्न है, शोषण की
इस चरण में किसी आन्तरिक बदलाव को अपनाये
जाने की जरूरत नहीं थी इसलिये आनवार पृथकता
की नीति इस काल की औपनिवेशिक नीति थी।

जहाँ तक प्राच्यवादी नीति की स्थापना का

प्रश्न है तो इसके कुछ स्पष्ट निम्नलिखित कारण रहे थे :

- औपनिवेशिक शोषण के पहले चरण में उपनिवेशवाद के लिये यह आवश्यक था कि वह क्लासिकल हिन्दू एवं इस्लामिक साहित्य के अंग्रेजी रूपान्तरण को बढ़ावा दे, जिसे प्राच्यवाद का नाम दिया गया। यह इसलिये जरूरी था क्योंकि अगर E.I.C. को भारतीय राजस्व के ऊपर अपने एकाधिपत्य की स्थापना करनी थी तब Classical ग्रन्थों के अंग्रेजी रूपान्तरण के बिना इस लक्ष्य को पूरा नहीं किया जा सकता था क्योंकि भूमि सम्बन्धी सभी नियम दस्तावेज, विनिमय संबंधी नियम उन्ही ग्रन्थो पर आधारित रहे थे। प्राच्यवाद की इस नीति के आधार पर उपनिवेशवाद के लिये वैसी नौकरशाही का निर्माण आवश्यक था जिसे इन स्थानीय बातों की जानकारी हो। क्योंकि जिसे राजस्व पुलिस एवं न्यायिक प्रशासन को जन्म दिया जाना था, यह तबतक संभव नहीं था जबतक इन प्राच्य व्यवस्थाओं की जानकारी उन्हें नहीं होती। प्राच्यवाद का यह दूसरा अर्थ भी है और दूसरा कारण भी।

- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर उपनिवेशवाद ने प्राच्यवाद को संरक्षण दिया तो इसका कारण एक ऐसे सामाजिक आधार की स्थापना रही थी, जो भारत में औपनिवेशिक जड़ो को मजबूत कर सकें। अगर उपनिवेशवाद को भारत में अपनी जड़ मजबूत करना था, तो उसे एक ऐसे

सामाजिक वर्ग को समर्थन चाहिए जिसका भारतीय समाज के अन्य समूहों पर पूरा नियंत्रण है और दूसरे, अगर नवोदित कंपनी राज्य को (3) स्थिरता प्रदान करनी थी तो गत्यात्मक ग्रामीण समाज एवं अगतिशील पिरामीड व्यवस्था का रूप ग्रहण करें। दूसरे लक्ष्य की पूर्ति के लिये वर्णाश्रम धर्म व जाति व्यवस्था कि जड़ो को मजबूत करना आवश्यक था तथा पहले लक्ष्य की पूर्ति के लिये सामाजिक पिरामीड के शीर्ष पर स्थित ब्राह्मणो को अपना समर्थक बनाने की जरूरत रही थी, इसलिये प्रथम चरण मे जिस औपनिवेशिक प्रशासन का (पुलिस, प्रशासन व न्यायव्यवस्था) विकास हुआ, इसमें ऊपर के कुछ पदो को छोड़कर बड़ी संख्या मे उन्हीं धर्म के प्रोफेसर्स (ऑफ हिन्दूज्म) को स्थान प्रदान किया गया। इस तरह कंपनी राज्य के निचे एक और राज्य की स्थापना हुयी जिसे प्रो० सुमित सरकार ने व्यंग से ब्राह्मण राज्य कहते है।

निष्कर्ष - अतः यह स्पष्ट है कि औपनिवेशिक विस्तार के इस दौर ने स्थानीय शासन को समाप्त कर दिया वही रूढ़ीवादी समाज के अभिजात्य वर्ग को संरक्षण प्रदान करने की नीति अपनायी